राष्ट्रीयकरण किया गया।

शिक्षक - रवि शंकर राय, अर्थशास्त्र -
दिनांक - 02-11-2020, वर्ग - BA - III

(ख) औद्योगिक नीति :- राजकीय पूँजीवाद के अन्तर्गत सोवियत सरकार की औद्योगिक नीति का लक्ष्य उद्योगों पर ऊपर तथा नीचे से नियंत्रण था। नीचे से नियन्त्रण (control from Below) लागू करने के लिए सरकार ने 14 नवम्बर 1917 को 'उद्योग पर श्रमिकों के नियंत्रण की आज्ञप्ति (Decree of the workers' control over Industry) जारी की। इसके अन्तर्गत श्रमिकों की समितियों को औद्योगिक प्रबन्ध पर निरीक्षण का अधिकार दिया गया। किन्तु उच्च अधिकारियों की स्वीकृति के बिना श्रमिकों द्वारा औद्योगिक संगठनों पर कब्जा किए जाने या उन्हें संचालित किए जाने पर रोक लगा दी गई। ऊपर से नियंत्रण (control from Above) लागू करने के लिए सरकार ने 18 दिसम्बर 1917 को जारी आज्ञप्ति में राजकीय एवं सामरिक दृष्टि से विशेष महत्व के उद्योगों, मजदूरी-नियंत्रण की अवहेलना करने वाले उद्योगों तथा निजी उद्योगपतियों द्वारा बन्द किए जाने वाले उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने की घोषणा की गई। इस आज्ञप्ति के अनुसार सर्वप्रथम

मई 1918 में चीनी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तदुपरान्त तेल, दियासलाई, कहवा, मसाले सूती ~~वस्त्र~~ वस्त्र एवं सामरिक उद्योगों तथा विदेशी व्यापार पर सरकार का एकाधिकार घोषित किया गया। राजकीय पूँजीवाद के काल में सरकार ने जिन थोड़े-से उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया, उसके पीछे उद्योगों को पूँजीपतियों के विनाश-प्रयत्नों (Sabotage) से बचाना था। जिन उद्योगों में विदेशी पूँजी विनियोजित थी, उनके लिए सरकार ने मिश्रित कम्पनियों के गठन की नीति अपनाई। मिश्रित पूँजी बैंको का राष्ट्रीयकरण करके 17 दिसम्बर 1917 को उन्हे स्टेट बैंक में विलीन कर दिया गया। निजी उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण हेतु दिसम्बर 1917 में सर्वोच्च आर्थिक परिषद् का गठन किया गया।

राजकीय पूँजीवाद का परित्याग ⇒ सोवियत सरकार ने नवम्बर 1917 से लेकर जून 1918 तक राजकीय पूँजीवाद की नीति का अनुसरण किया। जून 1918 में गृह-युद्ध आरंभ होने पर सरकार ने राजकीय पूँजीवाद की नीति छोड़नी पड़ी तथा सामरिक साम्यवाद की नीति अपनानी पड़ी। 28 जून 1918 को सामान्य राष्ट्रीयकरण की अज्ञप्ति जारी करते हुए सरकार ने सभी बड़े-बड़े उद्योगों का एक साथ राष्ट्रीयकरण कर डाला। जिन कारखानों

से 10 लाख रुबल से अधिक की पूँजी विनियोजित थी, उन्हें सरकारी अधिकार में ले लिया गया। तदुपरान्त सोवियत रूस में राष्ट्रीकरण की धूम सी मच गई तथा मार्च 1919 तक लगभग 9 हजार कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया। सोवियत सरकार द्वारा राजकीय पूँजीवाद की नीति का भी परित्याग निम्न कारणों से किया गया था—

(1) औद्योगिक क्षेत्र में अव्यवस्था—राजकीय पूँजीवाद के अन्तर्गत औद्योगिक नियंत्रण हेतु द्वैध शासन (Diarchy) की व्यवस्था की गई थी। श्रमिकों की समितियों को 'औद्योगिक प्रबन्धन पर नियंत्रण' का अर्थात उद्योगों पर नीचे से नियंत्रण रखने का अधिकार प्राप्त था। उद्योगों पर ऊपर नियंत्रण रखना सर्वोच्च आर्थिक परिषद का उत्तरदायित्व था। सरकार ने सामान्य राष्ट्रीयकरण के बजाय मिली उद्योगों पर कठोर नियंत्रण की नीति अपनायी थी। परन्तु औद्योगिक क्षेत्र में नियंत्रित पूँजीवाद की नीति सफल नहीं हो पाई। अनेक मजदूर समितियों ने सरकारी आज्ञा की अवहेलना करते हुए उद्योगों को अपने अधिकार में ले लिया। फलतः मिली

उद्योगपतियों के लिए काम करना लगभग असंभव-सा हो गया। यद्यपि मजदूर समितियों या स्थानीय सोवियतों द्वारा किए जा रहे अवैधानिक राष्ट्रीयकरण की रोकथाम के लिए सरकार ने भरसक प्रयत्न किया, किन्तु उसके आदेशों की निरन्तर अवहेलना होती रही। परिणामतः जून 1918 में जहाँ केन्द्र सरकार के आदेश द्वारा राष्ट्रीकृत फर्मों की संख्या केवल 100 थी; वहीं 400 से भी अधिक फर्में ऐसी थीं, जिनका राष्ट्रीयकरण स्थानीय संस्थाओं ने स्वेच्छा-चारितः से किया था। केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय-कृत फर्मों पर भी स्थानीय समितियों ने अपना अधिकार कायम रखा। मौरिस डॉब के अनुसार "यह क्रांति का प्रारंभिक काल था, जब अधिकांश कार्य असमन्वित स्थानीय प्रेरणा से सम्पन्न होते थे। ऐसी प्रारंभिक प्रवृत्तियाँ नई शासन पद्धति की शक्तियों का हिस्सा थीं, किन्तु इसका तात्कालिक प्रभाव अराजकतापूर्ण था।"